

विचार बिन्दु

ईश्वर एक शाश्वत बालक है जो शाश्वत बाण में शाश्वत खेल खेल रहा है। -अरविन्द

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने के स्थान पर समाधान तलाशें

अरविन्द कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ केस नं. W.P(C) 1246/2020 के केस में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने जा रहा है:-

(1) क्या पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 तथा 4 संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 तथा समानता के अधिकार को गारंटी का उल्लंघन करती है?

(2) क्या धारा 2, 3 व 4 अनुच्छेद 25, 26, और 29 तथा संविधान में धर्म निरपेक्षता की मूल विशेषता का उल्लंघन करती है?

(3) क्या आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किये गये मंदिर हिन्दू तथा इस्लामी पर्सनल लॉ के तहत मंदिर बने रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकायें उपरोक्त विषय पर फिलहाल तक नए हैं। राजनीतिक दलों जिसमें आरजेडी, एमआईएम, जयंत उलेमा-ए-हिन्द आदि हैं उन्हेोंने अपनी-अपनी पिढीतानुस में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि माननीय कोर्ट उक्त पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों का समर्थन करे ताकि देश में सभी लोगों में समरसता व भाईचारा बना रहे और कोई साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न नहीं हो, तथा संविधान का धर्मनिरपेक्ष ताना बना सुरक्षित रहे। पूजा स्थल अधिनियम अथवा उपसमायुक्त अधिनियम 1991 की अन्तर्गत प्रस्तुत की गई सभी पिढीतानुस को सुनवाई 2-3 होगी। इसे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बैंच सुनवाई कर रही है। केस में सुनवाई के हेतु 17 फरवरी 2025 को पेशी नियत है। अंग्रेजी में इस अधिनियम को प्लेसिज ऑफ वॉर्शिप एक्ट 1951 के नाम से पुकारा जाता है।

यह अधिनियम 18 सितम्बर, 1991 को संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम बाबरी मस्जिद के विध्वंस से एक साल पूर्व सन 1991 में लाया गया था। बाबरी मस्जिद के (खंडहर) को 1992 में गिराया गया था। अधिनियम का पूरा नाम पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 है। इस कानून को संसद में किसी भी पूजा स्थल के धर्मारोपण पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाये रखने के अधिनियम (उद्देश्य) से पारित किया गया था, जो जैसा भी 15 अगस्त, 1947 को था। सर्वोच्च न्यायालय उपसमायुक्त अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय करेगा। यह कानून जैसा ऊपर कहा है उपसमायुक्त को धार्मिक स्वरूप के बदलने से, जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, को रोकता है।

यह अधिनियम उस समय जन्ता के ध्यान में आया जब सर्वोच्च न्यायालय उस स्थान के सम्पत्ति विवाद का फैसला कर रहा था, जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। मस्जिद के खंडहर को, जिस रूप में वह उस समय थी, कार सर्वेको से 6.12.1991 को तोड़ा था। सिविल कोर्ट में सम्पत्ति का विवाद वर्षों तक चला था। दावे के अनुसार इस की सम्पत्ति का मालिकाना हक हिन्दुओं के देवता भगवान श्रीराम (रामलला) विराजमान का माना था। दिनांक 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 5 न्यायाधीशों ने उक्त सम्पत्ति का अधिकार माना था। इस प्रकार 450 साल पुराने विवाद का अन्त हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को वैधता को सुरक्षित रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा "पूजा स्थल अधिनियम आन्तरिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दायित्वों से संबंधित है यह सभी धर्मों की समानता के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" अरविन्द कुमार उपाध्याय की याचिका में उक्त एक्ट की धारा 2, 3 व 4 को संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 के मुख्य प्रावधानों को समझना प्रत्येक देश के नागरिक के लिये आवश्यक है। उपसमायुक्त अधिनियम, 1991 के अनुसार किसी भी उपसमायुक्त स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहना चाहिये जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। इसका उद्देश्य भी यही है कि पूजा स्थल के कथित ऐतिहासिक रूपान्तरण से उत्पन्न सभी विवादों को समाप्त करना है। धारा 3 स्पष्ट रूप से यह निर्देश देती है कि किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित करने की मनाही है या निरिवर्तन करने पर रोक है और रोक की स्थिति यह है कि उसी धार्मिक सम्प्रदाय के किसी अन्य भाग के पूजा स्थल में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 4(1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को था धारा 4(2) में बतलाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी भी उपसमायुक्त स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के बावत किसी भी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लिम्बत कोई भी वाद या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जावेगी और कोई नया वाद या कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकेगी। यदि 15 अगस्त 1947 के बाद इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी उपसमायुक्त स्थल का धार्मिक स्वरूप बदल गया है और उससे संबंधित कोई वाद या अपील किसी न्यायालय में लिम्बत है तो उसका निर्णय धारा 4(1) अनुसूच नहीं किया जावेगा। धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले से संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील अथवा कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। धारा 6 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है।

कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे जैसे - (1) वे पूजा स्थल जो प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित हैं। (2) यदि कोई वाद इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही अन्तिम रूप से निपटारा हुआ चुका है तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा। (3) उस स्थिति में भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा जब विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पहले ही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सौंपल दिया जा चुका है।

कबीर हिन्दू व मुसलमान दोनों के लिये पूजनीय थे। उन्हेोंने दोनों धर्मों के पाखण्ड पूर्ण व्यवहार पर करारी और तीखी चोट की थी। कबीर का मानना था कि हर इन्सान में ईश्वर का निवास होता है। उसे मंदिर-मस्जिद में ढूंढना सही नहीं है। ईश्वर न तो काबा में मिलेगा न काशी में बल्कि वह तो हर इन्सान में मिलेगा।

प्रक्रियात्मक साक्षात्कार के रूप में किसी धार्मिक चरित्र का पता लगाना वस्तुतः इस अधिनियम (एक्ट) की धारा 3 व 4 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता। कृष्ण ध्यान दें कि उक्त विचार किसी निर्णय का अंश नहीं है। यानी यह विवाद का विषय नहीं है। मधुरा एवं ज्ञान्यापी दोनों के विवादों में मस्जिद पक्ष के इस व्याख्या को चुनौती दी है। इसका यह अर्थ है कि उपरोक्त रिट याचिकाओं की बहस में यह प्रश्न उठाया जावेगा।

दिनांक 15 अगस्त 1947 भारत के लिये एक ऐतिहासिक व महत्व का दिन है, जब देश एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और संप्रभु राज्य बना था, जहां कोई राक्षस धर्म नहीं है और धर्मों को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है और नागरिकों को अपने-2 धर्म के रिवाजों, पद्धतियों के अनुरूप पूजा, साधना, उपसमायुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्र, अलग-2 धर्मों के पूजा स्थलों की यथास्थिति स्थापित रखने के लिये 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल एक्ट लागू किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि देश में आजादी के वक्त अर्थात् 15.08.1947 को जो पूजा स्थल किस स्थिति में थे, वे वैसा ही रहेंगे। पूजा स्थल अधिनियम सभी धार्मिक स्थलों पर लागू है चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का हो, उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में परिवर्तित नहीं कर सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई याचिकायें पेश हो रही थी, इसे देखकर न्यायालय ने मुद्दकमें बाजी पर विराम लगा दिया है। सभी अदालतों को निर्देश दिया है कि जब तक अपेक्स कोर्ट में मामले लिम्बत है तब तक अदालतें धार्मिक स्थलों के दावों के नये मुकदमों दर्ज नहीं करेंगे अथवा फाइनल आदेश पारित करेगी। सर्वे का भी आदेश नहीं देगी।

पूजा स्थलों का विवाद संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के तहत हल किया जाना चाहिये।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हिन्दू याचिकाकर्त्तों द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुये अपेक्स कोर्ट में प्लो ली थी कि अधिनियम के विरुद्ध याचिकाओं पर विचार करने से भारत में अनिश्चित मस्जिदों के विरुद्ध विवादों की बाढ़ आ जावेगी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी याचिकाओं का विरोध किया है।

जो याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं उनमें मुख्य तर्क यह है कि उक्त अधिनियम 1991 न्यायिक समीक्षा को रोकता है। धारा 4 न्यायालयों को विशेष मामले में निर्णय लेने से रोकती है। यह भी तर्क है और प्लो उदाह है कि चूकि न्यायिक समीक्षा को शक्ति संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है और उसे खण्डित नहीं किया जा सकता अतः अधिनियम वैध नहीं है। उक्त अधिनियम धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का भी उल्लंघन करता है। याचिका में एक्ट की वैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि अधिनियम (एक्ट) एक धार्मिक समुदाय को वरीयता देता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 का भी अतिक्रमण करता है। आर्टिकल 14 व 15 के तहत समानता और भेदभाव के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 के तहत भी इसे चुनौती दी गई है, जिसका संबंध जीने के अधिकार से है। जैसा ऊपर कहा है कि अधिनियम अनुच्छेद 25, 26 व 29 के तहत दिये गये धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

एक याचिका में तर्क है कि चूकि देवता शाश्वत होते हैं और मंदिर नष्ट करने के बाद भी मंदिर है, अतः मंदिर का स्थायित्व नष्ट नहीं होता।

वर्तमान में सर्वे से यह ज्ञात हुआ है कि हजारों मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिन्दुओं में जाग्रत आई है और वे तोड़े गये मंदिरों के स्थान पर पुनः मंदिरों को रेस्टोर (पुनः स्थापित) करना चाहते हैं। देश की अदालतें मंदिर/मस्जिद के विवादों से घिर जावेंगी और देश की संस्कृति और उसकी गंगा-जमुनी संस्कृति को भारी आधार होगा। सदभाव और भ्रातृ भाव में भारी तनाव पैदा होगा। अतः जो मुकदमों चल रहे हैं उनमें ऐसा निर्णय होना चाहिये जो राष्ट्रहित में हो। देश की एकता व अखण्डता अक्षुण्ण रहे। कुछ लोगों ने सलाह दी है कि हमें आपसी सदभाव से इन विवादों का हल निकालना होगा। यों तो मंदिर मंदिर में भेद नहीं हो सकता; किन्तु फिर भी भेद है और यह भी आस्था का प्रश्न है। मधुरा, काशी, सभल आदि कई स्थान के मंदिरों के विवाद आपसी सहमति से निपटारे जा सकते हैं। प्रयत्न करें कि विशिष्ट 12 मस्जिदों को अधिनियम की धारा 5 के तहत राम जन्मभूमि के मामले को तरह अपवाद में शामिल करें और शेष सभी मंदिरों के विवादों पर अधिनियम 1991 लागू किया जावे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मंदिर मस्जिद के केस को बहुत ही कुशलता व राष्ट्र की एकता व अखण्डता के हेतु निर्णित किया है जिसे देश का महान इतिहास सदा याद करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि (बाबरी मस्जिद) केस में उक्त अधिनियम की विवेचना की है और उसे अपवाद किया जाने को वैध माना है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाले तर्क सही हो सकते हैं और उस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है; किन्तु इससे राष्ट्र का अहित ही होगा, न्याय भी नहीं होगा। यदि देश के हिन्दू व मुसलमानों के मध्य कोई समझौता इस हेतु होता है तो वह चिर स्मरणीय होगा और इस घटना का इतिहास स्वर्णशतकों में लिखा जावेगा।

कबीर व मुसलमान दोनों के लिये पूजनीय थी। उन्हेोंने दोनों धर्मों के पाखण्ड पूर्ण व्यवहार पर करारी और तीखी चोट की थी। कबीर का मानना था कि हर इन्सान में ईश्वर का निवास होता है। उसे मंदिर-मस्जिद में ढूंढना सही नहीं है। ईश्वर न तो काबा में मिलेगा न काशी में बल्कि वह तो हर इन्सान में मिलेगा। कबीर ने कहा था- "मोको कहाँ ढूँढे रे बन्दे में तो तेरे पास में।"

न मंदिर में न मस्जिद में, न काबा कैलाश में।

कबीर ने कहा था, उसे पूजा स्थल में ढूंढना व्यर्थ है वह तो हर मनुष्य में है।

हे, खुदा व ईश्वर के बन्दे कबीर के दर्शन व भारतीय संविधान तथा संस्कृति को समझो और मंदिर-मस्जिद के इस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक गरिमा की छाया में आपसी सहमति से सुलझाने में इतिहास के साक्षी बने। सत्यमेव जयते।

-अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



राम शर्मा

हम वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था की चाल सकारात्मक रही। कई देशों में मंदी के बावजूद हमारी आर्थिक वृद्धि दर बनी रही। यूक्रेन-रूस युद्ध ने कुछ सेक्टर में महंगाई बढ़ाने का काम किया, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था ने संतुलित विकास किया है। अब यह देखना रोचक होगा कि भारत के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा? भारत के लिए अपनी युवा जनसंख्या, डिजिटल तकनीक और मजबूत होते आर्थिक वृद्धि के संयोजन हैं कि यह वर्ष भी भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोजगारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पूरा पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत को जलजल अर्थव्यवस्था कम रहने का अनुमान है, जिससे एक बड़ा कामकाजी वर्ग उत्पन्न होगा और उत्पादन को बढ़ावा देगा। 2025 तक भारत की श्रमशक्ति दुनिया में सबसे बड़ी हो सकती है, जो श्रम उपलब्धता के मामले में उसे एक विशिष्ट लाभ देगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत इस जनसांख्यिकीय लाभ को कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और रोजगार सृजन के माध्यम से भुनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

इस बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार न रहे।

भारत ने डिजिटल तकनीक के बुनियादी ढांचे में काफी प्रगति की है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से लाखों लोगों तकनीक का बेहतर उपयोग करने लगे हैं। 2025 तक, यह तकनीक लगभग हर क्षेत्र में जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। सरकार की कुत्रिम बुद्धिमत्ता (आईएफिल इंटेलिजेंस), मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देने की योजना, साथ ही साथ एक उभरते हुए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। फिनटेक, एडटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ेंगे, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल का निर्माण करना है। 2017 में लागू किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2025 तक कराधान प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करेगा, जिससे व्यापार लागत घटेगी और अनुपालन में सुधार होगा।

भारत की शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो अवसंरचना, आवास और परिवहन के लिए मांग को बढ़ावा देगी। स्मार्ट शहरों, मेट्रो रेल प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण अवसंरचना में बढ़े पैमाने पर निवेश से मजबूत आर्थिक विकास की नींव रखी जाएगी। वर्ष 2025 तक, भारत की अवसंरचना का विकास न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ावा देगा, जिससे एक अधिक कुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।

भारत का वैश्विक व्यापार में स्थान तेजी से बढ़ रहा है। देश ने विशेष रूप से आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और वस्त्रों के निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है। वर्ष 2025 तक, भारत वैश्विक निर्माण और सेवा केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। प्रमुख साझेदारों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण-एशिया के

साथ व्यापार समझौतों से भारत की आर्थिक स्थिति वैश्विक बाजार में और मजबूत होगी।

इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं होंगी। भारत में पर्याप्त श्रमशक्ति है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। हर हाथ को काम देना भारत के लिए इस वर्ष की बड़ी चुनौती होगी। कामकाजी उम्र की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन रोजगार बाजार जतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। इसके अलावा, श्रम कौशल अंतर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई श्रमिकों के पास उभरते हुए उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। वर्ष 2025 तक, सरकार और निजी क्षेत्र को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भारी निवेश करना आवश्यक होगा, ताकि एक ऐसे कार्यबल का निर्माण हो सके जो गतिव्यक्त रोजगार के लिए तैयार हो। यदि भारत इन मुद्दों को हल नहीं करता है, तो युवा बेरोजगारी आर्थिक वृद्धि को बाधित कर सकती है।

आर्थिक असमानता को दूर करना देश की बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समृद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। अमीर और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इस वर्ष में आय असमानता को दूर करना समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होगा। ऐसी नीतियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करें, असमानताओं को कम करें और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी कि वृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें।

भारत को गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन। देश का तेजी से औद्योगिकीकरण अक्सर उसके प्राकृतिक संसाधनों को कीमत पर हुआ है। वर्ष 2025 तक, भारत को सतत विकास पर अपने ध्यान को महत्वपूर्ण

रूप से बढ़ाना होगा, ताकि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और जलवायु संकट से निपटने में निवेश करना आवश्यक होगा। एक हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत की घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं दोनों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।

कृषि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश की बड़ी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, कृषि को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे निम्न उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अवसंरचना। वर्ष 2025 तक, यह जरूरी होगा कि सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों, बेहतर सिंचनाई प्रणालियों और बाजार लिंकेज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करे। ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और ऋण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करनी होगी, ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन को रोक जा सके और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जिनमें वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध शामिल हैं। संरक्षणवाद, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव जैसे मुद्दे भारत के विकास की संभावनाओं के लिए चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं। मजबूत कूटनीतिक उपस्थिति बनाए रखना और व्यापार संबंधों में विविधता लाना भारत को वैश्विक आर्थिक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इफ्) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

भारत-पाक सीमा पर बी.एस.एफ. ने "ऑपरेशन सर्द हवा" शुरू किया

बीकानेर, (निर्सं) राजस्थान से सटी करीब 1000 किलोमीटर लंबी भारत-पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट (सर्द हवा) शुरू हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि 26 जनवरी को देखते हुए सीमा की नियमित जांच होगी। बाहरी वाहन और लोगों पर विशेष नजर रहेगी। इस कड़ाके की टंड में जब जनता रजाइयों में दुबकी रहती है बीएसएफ के जवान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। ड्रोन से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना बीएसएफ के लिए चुनौती बनी हुई है। पिछले दिनों

गए हैं। ओपी जवान पर दो-दो तस्करो ने ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। उसके बाद से ही बीएसएफ बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड पर है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि 26 जनवरी पर विध्वंस फैलाने के उद्देश्य से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं या भारी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ भेज सकते हैं। इसे देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऑपरेशन अलर्ट के तहत सेक्टर मुख्यालय से भी जवानों को सीमा पर तैनात किया गया है सभी बटालियन के अधिकारी भी सीमा पर पहुंच गए हैं। हर 500 मीटर पर जवान तैनात किए

गए हैं। ओपी जवान पर दो-दो तस्करो ने ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। उसके बाद से ही बीएसएफ बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड पर है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि 26 जनवरी पर विध्वंस फैलाने के उद्देश्य से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं या भारी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ भेज सकते हैं। इसे देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऑपरेशन अलर्ट के तहत सेक्टर मुख्यालय से भी जवानों को सीमा पर तैनात किया गया है सभी बटालियन के अधिकारी भी सीमा पर पहुंच गए हैं। हर 500 मीटर पर जवान तैनात किए

मीटर तक नजर रखी जा रही है। सीमा पर पाक रेंजर्स की हरकत दिखाई देने पर कंट्रोल रूम से तत्काल कमांडेंट और अन्य अधिकारियों तक मैसेज जाता है। ड्रोन से हरोड्रोन और हथियार तस्करी को रोकने के लिए व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके लिए दो तरह के वाहन तैयार किए गए हैं जिन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। इन दोनों गाड़ियों पर करीब 10 जवान हथियारों से लैस होकर सीमा चौकी से 10

किलोमीटर तक के दायरे में 24 घंटे रेकी करेंगे। पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हथियार और मादक पदार्थ गिरा कर चले जाते हैं। बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट को देखते हुए बीएसएफ ने सीमावर्ती गांव में भी सर्विलांस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ग्राम रखक समितियों को भी अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि संदिग्ध दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में तत्काल पुलिस थाना या बीएसएफ चौकी पर सूचना दे।

लिव-इन में रहने वाली महिला को पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, याचिका खारिज

जोधपुर, (कासं) लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली शादीशुदा महिला को उसके पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जोधपुर फैमिली कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार स्थला निवासी एक महिला ने पारिवारिक कोर्ट में घरेलू हिंसा का परिवाद पेश किया था। महिला ने कहा था कि वह

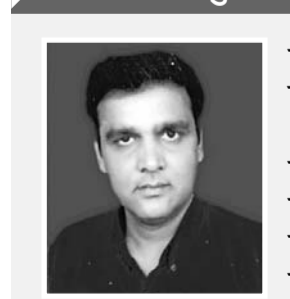
लंबे समय से पति से अलग रह रही है। नागौर के कुचेरा निवासी उसके पति का बिजनेस है। उसकी हर महीने की इनकम करीब सवा लाख रूपए है, इसलिए उसे तैयार रखना पर्याप्त है, जोधपुर फैमिली कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

जान में महिला का राजकुमार नामक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहना पया है। खुद महिला ने भी संबंधित कोर्ट में हुए बयानों में भी लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया। उसका

खर्च राजकुमार उठा रहा है। वहीं पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए दायर परिवाद में महिला ने कहा कि वह कोई काम नहीं जानती। पीहर पक्ष लंबे समय तक उसका भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह उन पर ज्वदा दिनों तक बोझ नहीं बने रहना चाहती है, इसलिए

उसे भरण-पोषण दिलाया जाए। सुनवाई करते हुए पारिवारिक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुहोहित ने महिला की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में दूसरे व्यक्ति की ओर से महिला का खर्च उठाया जाने के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में महिला को पहले पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार नहीं है।

राशिफल शुक्रवार 24 जनवरी, 2025



पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, अनुराधा नक्षत्र शनिवार प्रातः 5:08 तक, वृद्धि योग शुक्रवार प्रातः 5:08 तक, विष्टि करण सायं 7:26 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-धनु, गुरु-वृष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज सर्वार्थ सिद्धि योग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। भद्रा सायं 7:26 तक है। बुध मकर राशि में सायं 7:39 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:39 तक, लाभ-अमृत 8:39 से 11:19 तक, शुभ 12:39 से 1:59 तक, चर 4:38 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:58

मेष
चन्द्रमा अग्रम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मार्गात्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बचने लगे। विवाहित मामलों का निपटारा हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कर्क
परिजननों के व्यवहार के कारण मन-चिन्म हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक बृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कन्या
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
आर्थिक कारणों से अटक हुए व्यावसायिक कार्य बचने लगे। संभावित स्रोत से धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक बावों के लिए दिव्य अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक बृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में अंतोत्तप बना रहेगा। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

मकर
आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। अस्का हुआ धन भाव होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुम्भ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बचने लगेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बचने लगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।